



Neutral Citation No. – 2026:AHC:163864

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 30791/2026

श्रीमती चमन अंजुम और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद इमरान खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रफीउद्दीन अंसारी

न्यायालय संख्या- 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में व्यक्तिगत प्रतिवादी की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा निजी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।
3. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता एक परमादेश जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं, जिसके तहत प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के पति-पत्नी के रूप में शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हस्तक्षेप न करें। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और यह साबित करने के लिए उन्होंने अपने आधार कार्ड की कॉपी जमा की हैं। उन्होंने अपनी मर्जी और सहमति से शादी की है, बिना किसी दबाव के, और वे पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहे हैं। साथ ही, यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत प्रतिवादी और परिवार के दूसरे सदस्य नाराज़ हैं और उनकी जान को गंभीर खतरा है क्योंकि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और परेशान किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। याचिका में कही गई बातों का समर्थन याचिकाकर्ताओं के संयुक्त हलफनामों से होता है।

5. याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में यह दावा किया है कि वे पति और पत्नी के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उनकी हत्या कर सकता है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनके जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है।

6. जो आदेश पारित किया जाना है उसे देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, न्यायालय के नियमों के अनुसार इस रिट याचिका का यहीं पर अंतिम निपटारा किया जा रहा है।

7. सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह कानून तय किया है कि अगर लड़का और लड़की बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, तो उनके साथ रहने में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ तक कि उनके माता-पिता को भी नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के इन मामलों के फैसलों का हवाला दिया जा सकता है: ज्ञान देवी बनाम सुपरिटेण्डेंट,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; और भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396; जिनका सुप्रीम कोर्ट और इस कोर्ट ने लगातार पालन किया है, साथ ही इस कोर्ट के दीपिका और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 मामले के फैसले का भी। ज्ञान देवी (उपरोक्त) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है:

"7. ... याचिकाकर्ता की जन्म-तारीख चाहे जो भी हो, असल बात यह है कि अभी उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। चूँकि याचिकाकर्ता बालिग हैं, इसलिए वे किसके साथ रहना चाहती हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और न ही उनके रहने की जगह के बारे में कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। ऐसे मामले में न्यायालय या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी अपनी राय या पसंद को याचिकाकर्ता की राय या पसंद से ऊपर नहीं रख सकते।"

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं को साथ रहने की आज़ादी है और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में दखल देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा आती है, तो वे इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रतिवादी नंबर 2 से संपर्क कर सकते हैं, जो उन्हें तुरंत सुरक्षा प्रदान करेंगे।

9. निजी प्रतिवादी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कूटचितित या जाली हैं तो वह इस आदेश को वापस लेने के लिए एक पुनरावलोकन आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. सुप्रीम कोर्ट के (2006) 2 एससीसी 578 और (2008) 1 एससीसी 180 सीमा (श्रीमती) बनाम अश्वनी कुमार मामले में दिए गए फैसले के अनुसार शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए याचिकाकर्ता दो महीने के अंदर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने का वचन देते हैं। यदि याचिकाकर्ता ऊपर बताई गई तय समय-सीमा के भीतर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, तो इस आदेश के तहत दी गई सुरक्षा अपने आप खत्म हो जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की कथित शादी पर कोई फैसला नहीं सुनाया है और यह आदेश किसी भी तरह से उनकी शादी की वैधता के बारे में कोई राय ज़ाहिर नहीं करता है।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

5 अगस्त 2026

एस. अली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”